Expulsion of Indian Labourers from Gulf Countries

*228. SHRI S. MUTHU MANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether several illegal Indian labourers were expelled from UAE and other gulf countries during the year 1998;

(b) if so, the details thereof, alongwith the number of labourers so expelled;

(c) whether Government propose to assist them in getting back their employment; and

(d) if so, the details of the steps taken/ propose to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) to (d) In 1998, so far a total of 8,466 Indians, whose residence in their respective countries was considered illegal as per local rules, were served deportation orders. They included: 233 persons from the United Arab Emirates; 1,800 from Saudi Arabia; 5,633 from Oman; and 800 from Qatar.

Many of those deported have been able to return to the Gulf countries. To facilitate speedy completion of formalities, instructions have been given by Government for expeditious issue of passports.

भारत-नेपाल सीमा का सीमांकन

*229. **श्री ओंकार सिंह** लखावत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा का सीमांकन करने के लिए वर्ष 1981 में कोई समिति गठित की गई थी, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त समिति ने पिछले 17 वर्षों के दौरान सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार भारत-नेपाल सीमा के सीमांकन कार्य को कब तक पूरा करने का इरादा रखती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां। स्तम्भों के गायब हो जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने और अतिक्रमणों को दर्ज करने संबंधी निरीक्षण करने, जांच करने तथा उन्हें यथावत बनाए रखने से संबंधित कार्य का जायजा लेने और उसका समन्वय करने के लिए 1981 में भारत-नेपाल सीमा संबंधी संयुक्त तकनीकी स्तरीय समिति गठित की गई थी।

(ख) जी नहीं। संयुक्त समिति को सौंपे गए कार्य चालू प्रकृति के हैं। समिति द्वारा लिए गए संयुक्त निर्णय के अनुसार नियत सीमावर्ती सिद्धांतों से संबद्ध तटवर्ती भागों में सीमा तय करना, सीमा संबंधी स्तम्भों/प्वाइन्टों पर पुनः नम्बर अंकित करना और आधार नक्शे तैयार करने का काम पूर्व दिशा से एक-एक करके शुरू किया जा रहा है। फील्ड कार्यों की प्रगति की योजना जो संयुक्त रूप से तय की जाती है, की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है और यदि आवश्यक हुआ तो कठिन भू-भाग, तटवर्ती भागों की समस्याओं और उनसे पैदा होने वाले स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनका समय पुनः तय किया जाता है।

(ग) दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से तय की गई समय-सीमा के अनुसार भारत-नेपाल सीमा के सीमांकन का कार्य 2001 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

Uranium Mining in Singhbhum District of Bihar

*230. SHRI S.M. KRISHNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of Uranium produced from mines in Singhbhum (Bihar) during the last three years, year-wise;

(b) whether Government are aware of the increasing cases of serious ailments like cancer, physical disorders in Singhbhum and the reasons being rediation of redioactive rays due to uranium mining;

(c) if so, the safety measures taken in this regard; and

(d) whether a number of local agencies, villagers have been protesting against the mining, if so, whether Government would been the mining in the area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) It is not in the public interest to disclose information on the quantum of uranium produced in the country.

(b) and (c) No case of any increase in the incidence of ailments like cancer etc. for reasons attributable to uranium mining have come to notice. The Health Physics Unit of the Bhabha Atomic Research Centre monitors the environment, the flora and fauna and the human population in the vicinity of the uranium mines for radiation levels and effects, if any, on them.

(c) No, Sir.

राष्ट्रीय सिंचाई नीति

*231. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई राष्ट्रीय सिंचाई नीति का मसौदा तैयार किया है जिसके अन्तर्गत सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा की आधुनिक तकनीक उपलब्ध करायी जाएगी;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु योजना आयोग से अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) किन-किन राज्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में समुचित सिंचाई जल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जल नीति (1987) से भिन्न सिंचाई प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाने के वास्ते कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। उपरोक्त नीतिगत दस्तावेज को राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि मृदा नमी संरक्षण उपायों, ड्रिप सिंचाई, जल जमा करने की पद्धतियों तथा वाष्पीकरण हानियों को कम करने आदि तथा जल को कम खपत वाली फसलों को अपनाने आदि जैसे उपाय किये जाने चाहिए ताकि सूखा प्रवण क्षेत्रों पर सूखे से संबंधित समस्याओं का अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़े। उक्त नीति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् द्वारा इसे अपनाये जाने पर निर्भर करती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Per Capita Availability of Kerosene in Rajasthan

*232. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the per capita availability of kerosene in Rajasthan at present and its consumption with the national average; and

(b) the steps, so far, taken by Government to increase the allocation of kerosene to Rajasthan so as to increase the per capita availability in the State?

THE MINISTER OF PERTOLEUM AND NATURAL GAS (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) The per capita availability of kerosene in Rajasthan during 1997-98 was 8.22 kg./annum which was below the national average of 11.41 kg./annum.

(b) Allocation of kerosene is made on historical basis, i.e., past year's supplies plus additional allocation out of increase given at national level. kerosene is a deficit product and more than 40% of our requirements are met through imports. Requests are received from State Governments for additional allocation of kerosene from time to time. However, on account of constraints of product availability, foreign exchange and heavy subsidy involved, it is not possible to meet fully such demands always, possible increase, however, is given, out of the additional availability at the country level, in accordance with a formula, under which higher allocation, out of additional quantity, is given to states with lower per capita availability, so as to reduce inter-State disparity over a period of time. To take care of more deficit States, a very high increase has been given in the allocation of kerosene in 1998-99 to the States like Rajasthan